न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 37/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्राधिकृत अधिकारी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया आबूरोड जिला सिरोही जरिए प्राधिकृत अधिकारी श्री दीपक सागर।		1. मैसर्स एस. मनु स्टुडियो मकान नं. 01 वार्ड नं. 23, सरकारी अस्पताल के सामने आबूरोड जिला सिरोही। 2. श्री सुरेन्द्र चावडा पुत्र श्री नन्दकिशोर चावडा निवासी गांधीनगर, आबूरोड जिला सिरोही 3. श्री महेन्द्र चावड़ा पुत्र श्री नन्दकिशोर चावड़ा निवासी 899–ए, न्यू रेलवे कॉलोनी, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002

उपस्थिति :–

1. श्री गणपत कुमावत अधिकृत अधिकारी, प्रार्थी बैंक की ओर से ।

निर्णय

दिनांक : 23.09.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पक्ष के द्वारा अप्रार्थी

1. मैसर्स एस. मनु स्टुडियो मकान नं. 01 वार्ड नं. 23, सरकारी अस्पताल के सामने आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री सुरेन्द्र चावडा पुत्र श्री नन्दकिशोर चावडा निवासी गांधीनगर, आबूरोड जिला सिरोही
3. श्री महेन्द्र चावड़ा पुत्र श्री नन्दकिशोर चावड़ा निवासी 899–ए, न्यू रेलवे कॉलोनी, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात।

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:29:22 IST
Reason: SelfAttested

को राशि रूपये 04,00,000/– की ऋण [illegible] उपलब्ध कराई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी ने अपनी जायदाद [illegible] रखी थी। अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री नन्दकिशोर चावडा [illegible] जायदाद वाणिज्यिक सम्[illegible]टा नम्बर 16 दिनांक 25.07.1987 जो कि वार्ड नम्बर 20 गांधीनगर आबू[illegible]ला सिरोही में स्थित है, जिसकी माप 100 वर्गफीट है, को बैंक/कम्पनी के पक्ष मे रहन कर दिया।

जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी के बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से नोटिस दिनांक 29.11.2023 को जारी किये गये, जो पंजीकृत डाक/अखबार में प्रकाशन के माध्यम से तामिल करवाये गये उसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीयों के द्वारा बतौर जमानत रहन रखी गई सम्पति इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थी के लायक अधिकारी/अधिवक्ता की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता/अधिकारी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी एक नियमित निकाय है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से ऋण देने का व्यवसाय करती है उसकी शाखाओं मे से एक आबूरोड मे भी स्थित व कार्यरत है। प्रार्थी बैंक/संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को रूपये 04,00,000/– का ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक/कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र मे किया गया है। बहस मे कहा कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी पक्ष को नियमित रूप से ऋण राशि व ब्याज राशि का भुगतान नही करने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये किन्तु अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान नही किया गया। भुगतान नही करने के फलस्वरूप अप्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष मे रहन रखी गई उक्त जायदाद इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जावे।

प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी । अप्रार्थी द्वारा राशि रूपये 04,00,000/– का ऋण लिया था। ऋण राशि के बदले में अप्रार्थी द्वारा अपनी जायदाद को बैंक/कम्पनी के पक्ष मे उक्त जायदाद रहन रखी है । प्रार्थी द्वारा नियमानुसार धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिनांक 29.11.2023 को जारी किये है जिनकी प्राप्ति के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान नही किया है ।

दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 निम्न प्रकार है :–

14 . Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset – (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to the sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this Act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction any such secured asset or other document, relating thereto may be situated or found to take possession thereof and the

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:29:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राजस्थान)

जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Scanned with CamScanner

Chief Metropolitan Magistrate or as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him –

(a) take possession of such asset and documents relating thereto and

(b) forward such assets and documents to the secured creditor

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1) , the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may be take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

परिणामस्वरूप तथ्यों के संदर्भ मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ने अपनी जायदाद बैंक के पास बतौर अगानत बंधक रखी थी। अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री नन्दकिशोर चावडा ने अपनी जायदाद वाणिज्यिक सम्पत्ति पट्टा नम्बर 16 दिनांक 25.07.1987 जो कि वार्ड नम्बर 20 गांधीनगर आबूरोड जिला सिरोही में स्थित है, जिसकी माप 100 वर्गफीट है, को बैंक/कम्पनी पक्ष मे रहन कर दिया। जिसका अडौस–पडौस इस प्रकार है–

पूर्व – नगरपालिका की खुली भूमि।
पश्चिम – दुकान नम्बर 15
उत्तर – नगरपालिका भूमि व नाला।
दक्षिण – रोड़।

उपरोक्त जायदाद पर अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने की स्थिति में उक्त जायदाद का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस थाना से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाये जाने का आदेश दिया जाता है। यदि उक्त सम्पति किसी भी तरीके से बंद पायी जाती है, तो ताला तोडकर उक्त सम्पति पर प्रार्थी बैंक अपना कब्जा स्थापित करें। आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ पुलिस अधीक्षक सिरोही, संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। आदेश आज दिनांक 23.09.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:29:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner